

Regarding issues pertaining to rice millers*

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति महोदया, धन्यवाद ।

महोदया, मैं इस सदन का ध्यान आढ़ती और राइस-मिलर्स के मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

सभापति जी, वर्ष 2019-20 तक, जो हमारे आढ़ती हैं, उनका गेहूं और धान पर जो कमीशन था, वह एमएसपी के रेट का ढाई परसेंट फिक्स था । लेकिन, वर्ष 2019-20 के बाद सरकार ने उसे 46 रुपए-पर-क्विंटल पर फिक्स कर दिया ।

आप देखिए कि उसके बाद कितनी महंगाई बढ़ गई, चीजों के कितने रेट्स बढ़ गए । लेकिन, उनकी कमाई आज भी फिक्स है, जिस वजह से उन्होंने लास्ट इयर भी प्रोटेस्ट किया था । इस कारण हमारा प्रोक्योरमेंट का जो सीज़न था, उसमें भी डिस्टर्बेंसेज़ हुए ।

अतः मेरी सरकार से विनती है कि उनका कमीशन पहले की तरह, एमएसपी के रेट का ढाई परसेंट फिक्स किया जाए । दूसरा, जो राइस-मिलें हैं, उनमें पंजाब को स्पेस नहीं मिल रही है, जिस वजह से राइस की मूवमेंट नहीं हो रही है । इसके कारण हमारे गोदामों में स्पेस नहीं बन रही है ।

इसके कारण यह हो रहा है कि हमारे राइस-मिलर्स पहले मार्च-अप्रैल तक फ्री हो जाते थे, आज उनको छः-छः महीने ज्यादा लग रहे हैं । गर्मी का मौसम है, दाना टूट रहा है जिस वजह से करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है ।

माननीय सभापति : श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही जी ।

? (व्यवधान)